Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding issue of rising Air pollution in NCT of Delhi-laid.

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): प्रत्येक वर्ष अक्टूबर/नवम्बर माह में वायु प्रदूषण एक चिंता का विषय हो जाता है । अत्यंत प्रदूषित वायु से खच्चों एवं वृद्ध नागरिकों को फेफड़े, दमा इत्यादि जैसी समस्याएं हो रही हैं । दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण पर कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया । अपितु वह पंजाब एवं हरियाणा में होने वाली पराली की घटनाओं पर दोष डाल कर अपनी जिम्मेदारी से भाग जाती है । पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा की गई शोध के अनुसार दिल्ली के वायु प्रदूषण के मुख्य स्त्रोत औद्योगिक प्रदूषण (18%), वाहन उत्सर्जन (35%), निर्माण कार्य (30%) है । पराली से मात्र 7% प्रदूषण होता है । दिल्ली में लगभग 77.56 लाख पंजीकृत वाहन हैं जिनमें से मात्र 8.15 लाख वाहन सीएनजी चालित हैं । भारत सरकार द्वारा Eastern & Western Peripheral निर्माण से अंतर्राजीय भारी वाहन का दिल्ली में प्रवेश कम हुआ है । दिल्ली सरकार द्वारा अन्य वाहनों को सीएनजी में बदलने के लिए कोई प्रभावी प्रोत्साहन नहीं दिया गया है । इसी प्रकार निर्माण कार्य एवं औद्योगिक प्रदूषण के विषय में भी कुछ नहीं किया गया है । सुचारू सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था का दायित्व डीटीसी का है । इकॉनोमिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2010 में कुल 6204 बसें थी, परंतु आज सिर्फ 3760 बसें ही रह गई हैं । बसों के अभाव में लोगों को अपने निजी वाहन का प्रयोग करना पड़ता है जिससे प्रदूषण बढ़ता है । दिल्ली सरकार कथित रूप से पूरी तरह विफल रही है । हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा बसें खरीदने के अनुबंध में भी कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं । निर्माण कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा मात्र 75 टीमों का गठन किया गया है जो बहुत कम हैं । इसी प्रकार सड़कों से धूल हटाने के लिए पूरी दिल्ली में मात्र 69 वाहन है । इसी प्रकार बड़ी संख्या में हो रहे Construction & Demolition waste को वैज्ञानिक रूप से डिस्पोज करने के लिए निर्धारित स्थान पर परिवहन के लिए मात्र 192 वाहन हैं । दिल्ली सरकार का प्रदूषण के

विरूद्ध सिर्फ एक कार्य रह गया है और वह है कथित विज्ञापन (एवं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जनता के सरकारी पैसे से सैलरी देना । बजट का पैसा अपने प्रचार में खर्च होता है ।

प्रदूषण पर नियंत्रण मानवता का कार्य है । मेरा माननीय पर्यावरण मंत्री जी से यह अनुरोध है कि इस विषय पर विचार कर कुछ प्रभावी कदम भारत सरकार द्वारा उठाए जाएं जिससे वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष होने वाली 9 लाख मृत्यु को रोका जा सके ।